ACHIEVERS IAS ACADEMY

SUMMARY OF THE HINDU

FOR BPSC EXAMINATION

ENGLISH

DATE

02/02/2024

+91 8434931877, +91 7250667974

www.achieversiaspatna.co.in

Orchid Mall, Boring Road, (Opps.- A. N. College) Patna-800001

THE HINDU National

अंतरिम बजट 2024

1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 पेश किया।
जुलाई में आम चुनाव के बाद अंतिम बजट पेश किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार जुलाई में पूर्ण बजट के दौरान 2047 तक विकसित भारत के अपने दृष्टिकोण के लिए एक विस्तृत रोडमैप पेश करने की योजना बना रही है।
सुश्री सीतारमण ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार आने वाले वर्षों में भारत के पूर्वी हिस्से को विजन 2047 के तहत बनाना चाहती है।

बजट 2024 की मुख्य बातें

- **कुल व्यय अनुमानित 2024-**25 -47.66 लाख करोड़। 2024-25 के लिए उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 30.80 लाख करोड़ अनुमानित हैं।
- 2024-25 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% है।
- **राजकोषीय घाटा -** 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान - सकल घरेलू उत्पाद का 5.8%।
- सरकार ने 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 5.1% रखने का लक्ष्य रखा है।
- सरकार ने बजट 2023 में राजकोषीय घाटा 5.9% से कम रखने का लक्ष्य रखा था।

राजकोषीय घाटा = सरकार का कुल व्यय (पूंजी और राजस्व) - सरकार की कुल आय (राजस्व + ऋण वसूली + अन्य)

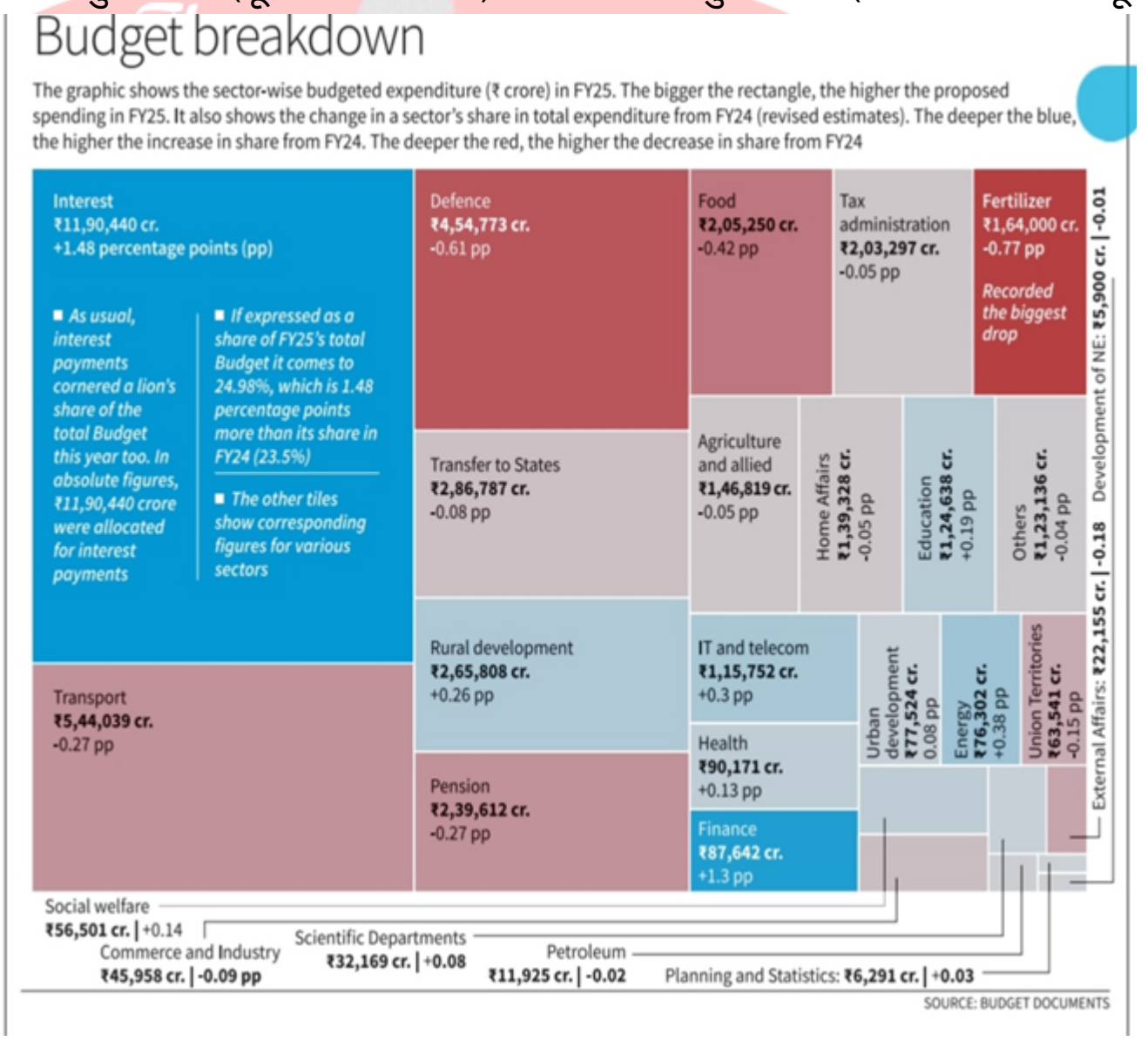

व्यय -

- पूंजीगत व्यय - 11.1% की मध्यम वृद्धि। 2024- 25 के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ है।
- ब्याज भुगतान - ब्याज भुगतान के लिए ₹11,90,440 करोड़ (+1.48% ऊपर) आवंटित किए गए।
- राज्यों को ऋण - राज्यों को ब्याज मुक्त कैपेक्स ऋण ₹1.3 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया

कर, पेंशन

➡ पुरानी पेंशन की मांग छोड़ेगी सरकार, छोटे वेतनभोगियों को मिलेगी राहत

- वित्तीय वर्ष 2009 -10 की अवधि के लिए ₹25,000 तक, वित्तीय वर्ष 20010 -15 की अवधि के लिए ₹10000 तक की कर मांगें वापस ले ली जाएंगी।

स्टार्टअप्स के लिए कर छूट की समाप्ति तिथि को एक वर्ष का विस्तार मिला

स्टार्टअप्स के लिए कर छूट की समाप्ति तिथि को एक वर्ष का विस्तार मिला

➡ महत्मा गांधी नरेगा

- बढ़ा हुआ आवंटन - मनरेगा के लिए ₹86,000 करोड़, यह पिछले बजट से 43.33% अधिक है।
- पिछले बजट में सरकार ने ₹60,000 करोड़ आवंटित किए थे, हालांकि ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार ने 2023-24 में ₹88,309 करोड़ खर्च किए।
  मनरेगा अभी भी समस्या का सामना कर रहा है, 1 फरवरी तक केंद्र पर राज्यों का ₹16,000 करोड़ बकाया है।
  सरकार ने भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल में इस योजना को निलंबित कर दिया है।

➡ स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग को ज्यादा पैसा मिलआ

- स्कूल शिक्षा विभाग के लिए कुल आवंटन ₹73,008.10 करोड़ है।
- पिछला बजट अनुमानित: ₹68,804 करोड़।
- उच्च शिक्षा के लिए ₹47,619.77 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- पिछले बजट में यह 44,094 करोड़ रुपये था
- पीएम श्री का आवंटन बढ़ा - पीएम श्री (स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) को लगभग 50% अधिक आवंटन, ₹6050 करोड़ मिला।
- पीएम पोषण (पीएम पोषण शक्ति निर्माण) जिसे पहले मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता था, को ₹12,467.30 करोड़ का आवंटन मिला।

➡ आशा, आंगनवाड़ी कर्मचारियों को स्वास्थ्य कवर मिला

- **आवंटन -** अंतरिम बजट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बजट को 2023-24 के 89,155 करोड़ से बढ़ाकर 90,658 करोड़ कर दिया गया है।
- **आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा -** आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवर को मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तक बढ़ाया जाएगा।
- **टीकाकरण के लिए यूडब्ल्यूआईएन पोर्टल** - नए डिजाइन किए गए यू विन पोर्टल का उपयोग "मिशन इंद्रधनुष" के तहत टीकाकरण के प्रबंधन और प्रयासों को तेज करने के लिए किया जाएगा।
- **एचपीवी टीकाकरण -** सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9-14 आयु वर्ग की लड़कियों के लिए एचपीवी टीकाकरण।
- **सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0 -** आंगनवाड़ी केंद्रों को "सक्षम आंगनवाड़ी" के तहत उन्नत किया जाएगा, जबकि पोषण वितरण में सुधार और प्रारंभिक बचपन की देखभाल और विकास सुनिश्चित करने के लिए पोषण 2.0 में तेजी लाई जाएगी।
- सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में सबसे अधिक ₹21,000 करोड़ का आवंटन हुआ।

केंद्र ने लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाया

- **1 करोड़ और बनाई जाएंगी 'लखपति दीदी' -** केंद्र ने 'लखपति दीदी' योजना का लक्ष्य मौजूदा 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया है।
- **लखपति दीदी योजनाएं -** इसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को अपने गांव के भीतर सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके कम से कम ₹1 लाख प्रति वर्ष की स्थायी आय अर्जित करने के लिए प्रशिक्षित करना है। वर्तमान में 83 लाख स्वयं सहायता समूह हैं जिनमें कुल 9 करोड़ महिलाएँ नामांकित हैं।

मध्यम वर्ग के लिए किफायती आवास योजना शुरू की जाएगी

- आवंटन - आवंटन.2024-25 के लिए आवास और शहरी मंत्रालय के लिए ₹ 77,523 करोड़ है।
- 2024-25 के लिए PMAY के लिए आवंटन ₹80,671 करोड़ है, जिसमें से ₹54,550 करोड़ PMAY (ग्रामीण) के लिए है।
- **किराये पर रहने वाले या झुग्गियों या चॉलों में रहने वालों के लिए योजना -** वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार "किराए के घरों या झुग्गियों या चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के योग्य वर्ग" की मदद के लिए एक योजना शुरू करेगी।
- **पीएमएवाई (ग्रामीण) के तहत अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ और घर -** महामारी के बावजूद पीएमएवाई (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। अगले पांच साल में दो करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य है.

कृषि एवं उर्वरक

खेती, मछली पालन के लिए आवंटन में मामूली वृद्धि

- **आवंटन -** कृषि मंत्रालय के लिए आवंटन ₹1,17,528 लाख करोड़ है। पिछले वर्ष से ₹1997 करोड़ की वृद्धि।
- प्रमुख योजनाएं हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), पीएम किसान सम्मान निधि (पीएम किसान)।
- पीएम किसान के लिए आवंटन ₹60,000 करोड़ पर ही बरकरार है।
- पीएम मत्स्य योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी मौजूदा योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

उर्वरक सब्सिडी में गिरावट तय, खाद्य सब्सिडी में बढ़ोतरी देखी गई

- उर्वरक सब्सिडी में गिरावट तय - बजट में उर्वरक सब्सिडी के लिए ₹1,64,150 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 2023-24 में यह ₹1,75,148 करोड़ था, संशोधित अनुमान ₹1,88,942 करोड़ था। 2022-23 में सब्सिडी 2.51 लाख करोड़ थी.
- नैनो यूरिया और नैनो डी अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) को सफलतापूर्वक अपनाने के बाद उर्वरकों की आवश्यकता कम हो जाएगी।
- खाद्य सब्सिडी (पीएम जीकेएवाई) - पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सब्सिडी और अन्य के लिए ₹2,05, 250 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- PM GKAY के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है.

शक्ति

➡ 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली देंगे सोलर पैनल

- 1 करोड़ घरों को मिलेंगे रूफटॉप सोलर पैनल - सरकार घर पर 1 करोड़ रूफटॉप सोलर पैनल लगाएगी। हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सकेगी, इससे इन परिवारों को सालाना ₹15,000 से ₹18,000 का लाभ होगा। अतिरिक्त बिजली बिजली वितरण कंपनियों को बेची जाएगी।
  हालाँकि यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि सरकार इन्हें वित्तपोषित करेगी या सब्सिडी देगी।
  वर्तमान में भारत में लगभग 11 गीगावॉट स्थापित छत सौर क्षमता है, जिसमें से केवल 2.7 गीगावॉट आवासीय इकाइयों में है।

आधारभूत संरचना

➡ सड़क क्षेत्र में 2.7% की मामूली बढ़ोतरी देखी गई

- आवंटन - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को बजट अनुमान 2,70,434 करोड़ की तुलना में 2,78,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- भारत माला - सड़क और परिवहन मंत्रालय को कुल आवंटन में से ₹1,68,000 करोड़ भारत माला परियोजना के लिए आवंटित किए गए हैं। नवंबर 2023 तक कुल 26,418 किमी में से 15,045 किमी सड़क पूरी हो चुकी है। भारत माला परियोजना के तहत कुल 4.1 लाख करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं

भारत माला परियोजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके तहत 550 जिला मुख्यालयों को न्यूनतम चार लेन सड़क से जोड़ा जाएगा। सरकार की लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना है। इसका लक्ष्य 80% माल यातायात (वर्तमान 40%) को इनके माध्यम से स्थानांतरित करना है।

➡ तीन आर्थिक रेल गलियारे विचाराधीन

- **आवंटन -** वित्तीय वर्ष 2024 - 25 के लिए रेलवे को ₹2.55 लाख करोड़ आवंटित किया गया है, जो पिछले वर्ष से 5.8% अधिक है।
- **तीन प्रमुख आर्थिक गलियारा कार्यक्रम :-** वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार तीन प्रमुख आर्थिक गलियारा कार्यक्रम लागू करेगी।
- **ऊर्जा आर्थिक गलियारा -** ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा।
- **रेल सागर :-** पोर्ट कनेक्टिविटी कार्यक्रम
- **अमृत चतुर्भुज -** उच्च यातायात घनत्व गलियारा

इनके तहत 11 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली कुल 434 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

- **वंदे भारत मानक के अनुरूप 44,000 कोचों की मरम्मत की जायेगी ।** अगले पांच वर्षों में यात्रियों को वंदे भारत ट्रेनों के समान विशेषज्ञ देने के लिए 44,000 कोचों की मरम्मत की जाएगी।
- **पीएसयू में निवेश घटा -** सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के लिए बजट आवंटन 2023-24 में ₹34,353 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹31,101 करोड़ हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह निजी क्षेत्र के लिए बाजार खोलना है।
- बुलेट ट्रेन आवंटन पिछले ₹19,592 करोड़ से बढ़कर ₹25,000 करोड़ हो गया।

➡ UDAN हिट और एयरपॉकेट, बजट आवंटन में 60% की कटौती।.

- आवंटन - नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए आवंटन 26% घटकर ₹2300 करोड़ हो गया।
- उड़ान योजना के लिए आवंटन 60% घटाकर ₹502 करोड़ कर दिया गया है। पिछले बजट में ₹1502 करोड़ आवंटित किए गए थे।
- वित्त मंत्री ने कहा कि देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई। पांच सौ सत्रह नए मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को ले जा रहे हैं। भारतीय विमानन कंपनियों ने 1000 नए विमानों का ऑर्डर दिया है.

➡ उद्योग जगत इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने की योजना का स्वागत करता है

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र इलेक्ट्रिक चार्जिंग इकोसिस्टम का समर्थन करके इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क बसों को अधिक से अधिक अपनाने पर भी जोर देगा

अनुसंधान एवं विकास, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी

➡ केंद्र ने अनुसंधान एवं विकास के लिए ₹1 लाख करोड़ के कोष पर विचार किया

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि निजी क्षेत्र को "सनराइज सेक्टर" के अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए "न्यूनतम" या "शून्य" ब्याज दरों पर ₹1 लाख करोड़ का कोष उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण ब्याज मुक्त होंगे। पांच दशक.
- राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लिए ₹2,819 करोड़ अलग रखे गए हैं।
- सनराइज सेक्टर - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, स्पेस इकोनॉमी, जीनोमिक्स और फार्मा, क्लीन मोबिलिटी, फूड प्रोसेसिंग सनराइज सेक्टर में से हैं।

➡ कार्डों पर बिप विनिर्माण, बायो फाउंड्री के लिए नई योजना

- बायोटेक्नोलॉजी की एक नई योजना - + एफएम ने "बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर, बायो प्लास्टिक, बायो फार्मास्युटिकल और बायो एग्रो इनपुट जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्प" प्रदान करने के लिए "बायोमैन्युफैक्चरिंग और बायोफॉड्री की एक नई योजना" की घोषणा की।

यह सरकार के दृष्टिकोण का एक हिस्सा है कि जैव अर्थव्यवस्था 2030 तक 300 बिलियन डॉलर का योगदान देगी, जो मौजूदा स्तर से 18 लाख करोड़ रुपये अधिक है। 2047 का लक्ष्य है कि जैव अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देगी।

➡ अंतरिक्ष कार्यक्रमों में नाममात्र 4% की बढ़ोतरी

- आवंटन - अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए आवंटन मामूली बढ़ाकर ₹13043 करोड़ कर दिया गया है, पिछले बजट में ₹12,525 करोड़ आवंटित किया गया था।
- इस साल एनआईएसएआर मिशन लॉन्च होने की उम्मीद है, साथ ही गगनयान मिशन के लिए कई परीक्षण भी किए जाएंगे।

➡ समिति "तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तन" का अध्ययन करेगी: एफएम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को घोषणा की कि "तेजी से जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय चुनौतियों" से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को देखने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट में कहा।

समिति को विकसित भारत के लक्ष्य के संबंध में इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सिफारिश करने का काम सौंपा जाएगा।

एफएम ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बदलती जनसांख्यिकी भी चिंता का विषय है।

World

यूरोपीय संघ यूक्रेन के लिए 50 अरब यूरो के राहत पैकेज पर सहमत हैe

यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों ने यूक्रेन को उसके आर्थिक पुनरुद्धार के लिए 50 बिलियन यूरो (54 बिलियन डॉलर) का नया सहायता पैकेज प्रदान करने के लिए गुरुवार को एक समझौते पर मुहर लगाई। यह पैकेज 2024 -27 तक चलेगा।

यूरोपीय संघ के नेता दिसंबर में इस पैकेज पर सहमत हुए थे, लेकिन हंग्री ने वीटो कर दिया था, हंग्री ने बुधवार को अपना वीटो हटा लिया। लेकिन इस बार हंग्री पैकेज पर सहमत हो गई।

"यूरोपीय संघ की निरंतर वित्तीय सहायता दीर्घकालिक आर्थिक को मजबूत करेगी और वित्तीय सहायता दीर्घकालिक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करेगी"

भारत यूएनआरडब्ल्यूए स्टाफ के हमास हमले से जुड़े होने को लेकर चिंतित है

भारत ने गुरुवार को 7 अक्टूबर के हमास हमले में यूएनआरडब्ल्यूए कर्मचारियों की संलिप्तता पर 'गहरी चिंता' व्यक्त की।

यह बात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कही.

पेगासस जॉर्डन में पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के फोन हैक करता था

डिजिटल राइट्स ग्रुप एक्सेस ने गुरुवार को कहा कि पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जॉर्डन में पत्रकार और वकील मानवाधिकार कार्यकर्ताओं सहित कम से कम 30 लोगों के खाते को हैक करने के लिए किया गया था।